



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 1983/वैशाख 13, 1905

No. 74]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 1983/VAISAKHA 13, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 15-आई०टी०सी० (पी०एन०)/83

नई दिल्ली, 3 मई, 1983

विषय.—1981-82 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त येन 2/134 बिलियन (येन 2,134,653,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान-सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

मिलिश सं० आई०पी०सी०/23(1)/83 से जारी —1981-82 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त येन 2,134 बिलियन (येन 2,134,653,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तों को लागू होने वाली जैसी शर्तों (1-10-1981 से 30-9-1982 तक) इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं के जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

सीमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक

सार्वजनिक सूचना संख्या 15-आई०टी०सी० (पी० एन०)/83  
दिनांक 3 मई, 1983 का परिशिष्ट

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1981-82 के लिए 1-10-1981 से 30-9-1982 तक 2,134 बिलियन (येन 2,134,653,000)

(ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

### खण्ड-1 : सामान्य शर्तें

1 (1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2,134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता भारत के अलावा ओ०ई०सी०डी० और विकास-शील देशों के हक में संगठित की गई है। तबनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस अनुदान के अंतर्गत पात्र छोट वेश होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मर्दे आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबंध 2 में दी गई है।

1 (2) लाइसेंस पर एक वार्षिक 1981-82 के लिए 2,134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता होगा। प्रथम और विंतीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एन०/जे० एन०" होगा ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण के लिए आयात लाइसेंस के अंतर्गत पत्र में भी बुद्धिगए जाएंगे।

1 (3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकृत के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अधिकर्ता को भारतीय स्वयं से चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1 (4) आयात लाइसेंस लागत बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारंभिक वेश अवधि के साथ जारी किया जाएगा।

लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंस धारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो इस मामले में आधिकार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1 (5) पक्के आदेश अनुबंध 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर अवर सचिव (टीए) आधिकार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों का क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिबद्ध हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिबद्ध हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकारियों के आदेश और/या भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकारणीय नहीं है।

1 (6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1 (5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव विरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय आधिकार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत लदाव के लिए आखिरी तिथि नियमित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1984 के बाद की न हो।

**खण्ड-2 संभरण ठेके का समाप्ति करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:—**

2. (क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या यू० एस० डॉलर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेट या एक पेरी से कम की मात्रा के बिना ही अधिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अधिकारों का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत-बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्च वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निविष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

2 (2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि

की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए।

### 2 (3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र होत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र क्षेत्र देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

**खण्ड-3 संभरक निम्नलिखित ठेकों की शर्त विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए।**

3 (1) 1981-82 के लिए 2,134 विनिधान के अनुदान महायन्त्र से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 1 फरवरी, 1983 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है।

3 (2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र" (ए०पी०) के माध्यम से किया जाएगा जो 1981-82 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अर्धवर्षिक बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग, यू०सी०ओ बैंक लिमिटेड पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3 (3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3 (4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय वृत्तावास टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उनके लिए संबंधित माल की मुद्रणी के कार्यक्रम की भारतीय वृत्तावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय वृत्तावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में जहां भारतीय आयातक सहायता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक ब्योरे देने हुए पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए। और उसकी एक प्रति भारतीय वृत्तावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

### **खण्ड-4 : भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :**

4 (1) जैसे ही आदेशों को अन्तिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिबद्ध हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र पाम संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ समुद्र पार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध 3 के प्रपत्र में "ए०पी० जारी करने के आवेदन" की 2 प्रतियों सहित संगतबद्ध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव (टी०ए०) आधिकार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रतियां संविदा की विषयवस्तु या उसकी कोमन के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होंगी।

4 (2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी" जारी करने के लिए 'आवेदन पत्र' और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आधिकार्य विभाग) जापान अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज को एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजवृत्तावास टोकियो और भारत में जापान के राजवृत्तावास को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4 (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, पानिपत स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए अनुबंध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी)" जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो आयातक भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

4 (4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान की सरकार भारत के राजदूतावास टोकियो आयातक के भारत में बैंक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इन प्राप्ति की सूचना से संभरकों को अवगत कराएगा।

4 (5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरकों अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि का विदेशी संभरकों को उमने बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

4 (6) संभरकों के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिये बैंक आफ इंडिया, टोकियो को वेप बैंक खर्च, भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

#### खण्ड-5: रुपया जमा करने का उत्तर-दायित्व:

5 (1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध-3 के अंश में उल्लिखित है) की शाखा होगी उन बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरकों को चुकाई गई येन/यू.एस. डालर/पौण्ड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभरकों को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरकों बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक हों की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरकों को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखों में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी(पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन/यू.एस. डालर/पौण्ड धनराशि के बराबर रुपया की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 17-1-78 में निर्धारित मुद्रा, विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम निर्देशन परिपक्षों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होना अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही वेप धनराशि सरकारी लेखों में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि अपने बैंकों के दस्तावेज लेने से पहले ही वेप धनराशि लेखों में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिसे लेखा गोप्य

में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट एण्ड एक्वालिज-843-निधिय डिपोजिट-डिपोजिट्स कोर परचैजिंग एमेडा एवाड परचैजिंग ग्रान्ट एंड फ्राम गवर्नमेंट आफ जापान फार 1981-82) येन 2,134 विनियम ग्रान्ट एंड-अण्ड सहायता।

5 (2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की शाखा में मकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपमगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (ड्रुडिफिकर्सी) से प्राप्त एक ड्रुडो (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (ड्रुडो ग्राहक और प्राप्त) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पीएन)/67 दिनांक 30-8-68, सं० 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68 सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में निर्धारित सरकारी लेखों में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5 (3) सरकार द्वारा गेसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक की ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। जालान के विभिन्न कालों को भरने समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी(पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी(पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना जालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्योरे" में निरपवाद रूप में निर्विष्ट किए गए हैं। खजाना जालान में निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप में प्रस्तुत करने चाहिए:—

- (क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक
  - (ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।
  - (ग) विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि।
  - (घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना जाएगा।
  - (ङ) जमा की गई कुल धनराशि।
- (ब्याज की गणना विदेशी संभरकों को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखों में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है।)

इसके पश्चात् सी०ए०ए०एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संबंध देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना जालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:— भारत में आयातक के बैंक का यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपया का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के वस दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5 (4) भारत में सम्बद्ध बैंक आफ इंडिया, को लाइसेंस की मुद्रा विनियम निर्देशन प्रति दर रुपया निवेशों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया को भेजना चाहिए।

खण्ड—6 : विविध शर्तें :—

6(1). आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्टें :

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोटलवानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोटलवान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी०ए०ए० एण्ड ए० आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संमद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2). संभरकों को विशेष शर्तें अखिलस्थित करना :

लाइसेंस धारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरकों को अवगत करावें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

6(3). विवाद :

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस धारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तर वायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें साफ-साफ "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबन्ध-1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

6(4). भविष्य अनुदेश :

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित जापान से 1981-82 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5). अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-नियति (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

6(6). अनुबंधों की सूची :

अनुबन्ध—1 पात्र स्तरीय देशों की सूची

अनुबन्ध—2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबन्ध—3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबन्ध—4 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र

पात्र स्तरीय देशों की सूची

(क) आ०ई०सी०डी० देश :

आस्ट्रेलिया	बेलजियम
कनाडा	डेनमार्क
फिनलैंड	फ्रांस
जर्मनी संघीय गणराज्य	यूनान
आईसलैंड आयरलैंड	इटली
जापान	लगजम्बर्ग
दी नीदरलैंड	न्यूजीलैंड
नार्वे	पुर्तगाल
स्पेन	स्वीडन
स्वीटजरलैंड	सुर्की
दि यूनाइटेड किंगडम	और यूनाइटेड स्टेट्स

(ख) सकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नाम-ओ०पी०ई०सी० विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र मोरॉको

सुतीशिया

2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा

अंगोला

बोत्सवाना

बुरुन्डी

कमरून

केप वर्डी द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीकन गणराज्य

जाद

कमोरी द्वीप समूह

इथोपिया

जाम्बिया

कांगो, दमोह गणराज्य

इक्वेटोरियल गाईना

षाना

गिनी

आइवरी कोस्ट

कीनिया

लेसोथो

साइबेरिया

मालागासी गणतंत्र

मालावी

माली

माली

मारिसेनिया

मारीशस

मोजम्बीक

नाइजर

पुर्तगाल गिनी

रियुनियन

रोडेसिया

रवांडा

सेंट हेलेना और जेप (2)

सोमोटोम प्रिन्सिपी

सेनेगल

सिचिलीज

सियरा लियोन

सोमालिया

सूडान

स्वाजीलैंड

टेर्रा अफार्स और इसास

टांगो

युगान्डा

तम्बानिया गणतंत्र संघ

अपर वोल्टा

आयरे गणतंत्र

जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बेल्जामास

बारबाडोस

बेलाइज

बरमुडा

कांस्टोरिका

क्यूबा

ओमिनिकन गणतंत्र

एल्साल्पेडोर

गुवाडेलोप

ग्वाटेमाला (\*)

हैती

होम्बर्स

जेमैका

मार्टिनिक-क्यू

मैक्सिको

नीदरलैंड एंटिलीज

निकारगुआ

पनामा

सेंट पियरी और मिक्यूलोन

ट्रिनिडाड और टोबागो

(1) पहले स्पेनीश गिनी का प्रदेश. फरना-ओ पो द्वीप समूह।

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : असेणान, ट्रिस्टन डा इन एन्सेसिबल्स, नार्थवैल गफ। ]

(3) मैन समूह, अरना, बोनाहुरे, क्यूराकाओं, साहा, सेंट मुस्तासिट, सेंट मार्टिन (दक्षिण भाग)।

## अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय (क्रमशः)

वेस्ट इण्डियन भाषा (एन आई ई)

(क) संबंधित राज्य (1)

(ख) आश्रित राज्य (2)

## 4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना

बोलिविया

ब्राजील

चिली

कोलम्बिया

फोल्कलैंड द्वीप समूह

फ्रांसिसी गिनी

गुयाना

पाराग्वे

पेरू

सूरिनाम

उरुग्वे

## 5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन

इजराइल

जोर्डन

लेबनान

ओमान

सिरियाई अरब गणतंत्र

यूनाइटेड अरब एमिरात

यमन अरब गणतंत्र (3)

यमन जनवादी ग्री आर (4)

## 6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान

बांग्लादेश

भूटान

बर्मा

मालदीव

नेपाल

पाकिस्तान

श्रीलंका

## 7. सहार पूर्व एशिया

म्यांमार

मंगोलिया

खमर गणतंत्र

कोरिया गणतंत्र

लाओस

मकाओ

मलेशिया

फिलीपीन्स

सिंगापुर

ताइवान

थाईलैंड

तिमोर

वियतनाम गणतंत्र

वियतनाम जनवादी गणतंत्र

## 8 ओसिनिया

कोक द्वीप समूह

गिनी

गिल गिल्बर्ट और टर्नाट द्वीप

फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)

मोरो

न्यूकोलेडोनिया

म्यूहेंबरीसिस (त्रि और फ०)

हिंदू

पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य 6)

पापुआ न्यू गिनी

सोलोमन द्वीप समूह (त्रि)

टोंगो

वालिस और फुतुना

पश्चिम समाओ

## 9. यूरोप

साइप्रस

जिब्राल्टर

ग्रीक

माल्टा

स्पेन

युर्की

यूगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप एष्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, सेन्ट किट्स, सेन्ट क्रिस्टोफे, नेविस अंगुइला, ग्रेट लुसिया और सेन्ट विन्सेंट।

(2) सैन आई लैम्ब, मोन्ससेराट, गैमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिस धरजिनद्वीप समूह।

(3) अजमन, बुनई, फूजाइर, रास अल खैमाह, शेरजाह और उम्मल क्वैबैन।

(4) अबन और विभिन्न सलतनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी आई लेइव् समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आइल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्कोस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मैरश द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(खण्ड - 2) ओ०पी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया

बोसनिया

सीरियाई अरब गणतंत्र

गैबान

नाइजीरिया

हर्षेडोर

नेजुएला

ईराक

ईराक

कुवैत

कातार

मऊदी अरब

आबू धाबी

इन्डोनेशिया

अनुबन्ध -- 2

## पात्र पत्र सूची

1. रोज़।
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात।
3. ट्रकों और ट्रेक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे।
4. रसायन।
5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल।
6. बिजली के हलों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे।
7. मशीनरी, संघटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माल।
8. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनरी और उपस्कर।
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिये मशीनरी, उपस्कर और फालतू पुर्जे।
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मवे जिन पर आपन में सहमति हो।

अनुबन्ध-3

“सुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करण के लिए प्रार्थना-पत्र”

सं०

दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग,

यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,

पालियामेंट स्ट्रीट,

नई दिल्ली-110001

विषय :— 1981-82 के लिए 2,134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता योन के अधीन जापान से आयात।

सहोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान ने जो कि आयात के संबंध में हे सम्बद्ध सभरक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया,

टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :-

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।
- (ख) आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है ।
- (ग) प्राप्त के तरीके—क्या यह सीधे कच्चा या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण तब यह संकेतित होना चाहिए कि क्या निविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकसीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।
- (ङ) माल का उद्देश्य देश ।
- (च) निविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में) ।
- (छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमरेशन की धनराशि ।
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।
- (झ) संभरकों के साथ की गई निविदा की संख्या और दिनांक
- (ञ) संभरक का नाम और पता ।
- (ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको निविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।
- (ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याभूति तिथि
- (ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाने हुए ।
- (ड) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पोर्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निविष्ट कीजिए) ।
- (ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।
- (त) क्या उरी लाइसेंस के अंतर्गत निविदा (निविदाओं) कर दी गई है । यदि हा, तो ऐसी निविदा की दिनांक और मूल्य ।

भवदीय

अनुबन्ध 4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक ऑफ इण्डिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय:—2.134 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न ब्यौरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्वे श्री—  
के नाम में—  
येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकृत पत्र (ए/पी) की पावनी के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए ।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लवान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लवान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक को बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है ।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र—  
तक वैध रहेगा ।

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक:—  
को उनके पत्र सं०  
दिनांक—  
के संदर्भ में ।

2. आयातक का बैंक—  
—उत्तसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो, जोच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन/यू एस डालर/पौंड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई टी सी (पी एन )/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना को समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में मुख्य रूप से जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन )/76 दि० 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से व्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा । व्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह लिपि जिसकी विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह लिपि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है । (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी) । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है ।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया सीमा हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुपंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आवाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी ट्रेण्डी के माध्यम से करनी चाहिए । हम संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 23-आई टी सी (पी एन )/68 दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन )/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन )/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन )/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिनाया जाता है । लेखा शीर्ष जिनमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपॉजिट्स एंड एक्सासिज-843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार फरवर्डिंग एटसेक्रेट्री एग्नाइड-परवेजिस ग्रांड एंड फाम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1981-82 (येन 2.134 बिलियन ग्राट एंड डेविट रिस्कीफ)" ।

जिन मामलों में मुख्य रूप से रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, नोन हजारी में गार्यजनिक सूचना स 132-आई टी सी (पी एन )/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की सूच रूप में एक पत्रलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देने हुए, अधेष्टण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पत्र पर भेजी जाएगी.—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), पहली मंजिल, ए सी ओ बैंक बिल्डिंग, संगम मार्ग, नई दिल्ली।

जिन मामलों में मुख्य रूप से ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्णों द्वारा प्रेषित करता है उसकी सूचना उपर्युक्त पत्र पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में व्याज की शुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए मुख्य रूप का पूरा ब्यौता इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संवरक के बैंक के खर्चों सहित सयवि कोई हो तो, बैंकिंग खर्च और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्च इंडिया बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निश्चित किए जाएंगे।

4 भारतीय दूतावास, टोकियो।

5 अवर सचिव (टी ए ) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE

### IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 15—ITC(PN)|83

New Delhi, the 3rd May, 1983

Subject.—Licensing conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.134 Billion (Y 2,134,653,000 (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan.

Issued from file No. IPC|23(1)|83.—The terms and conditions governing the licensing conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.134 Billion (Y 2,134,653,000) (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan (from 1.10.81 to 30.9.82) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports and Exports

## APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 15|ITC(PN)|83 DATED THE 3RD MAY, 1983.

Licensing conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese grant aid of Yen 2.134 Billion (Y 2,134,653,000) (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan (from 1.10.81 to 30.9.82).

### Section I—General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.134 billion extended by the Government of Japan is untied in

favour of OECD and developing countries except India. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.134 billion Japanese Grant Aid for 1981-82". The licence code for the first and second suffix will be "S|JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date or shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1984.

**Section II.—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract.**

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. *In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.*

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

**II (iii) Eligibility of Supplier**

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

**Section III**

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 1st February, 1983 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.134 billion for 1981-82 "and will be subject to the approval of Government of India".

III (ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1981-82.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III (iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo

informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer requires this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

**Section IV.—Contract Approval by Govt. of India.**

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Japan Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV (iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV (v) The foreign supplier shall, after affecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.



## Section V.—Responsibility for rupee deposit.

V (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (0) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US\$/Pound Sterling Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16.6.76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12.10.1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US\$/Pound Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17.1.1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. *It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers.* The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is 'K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad purchase Grant Aid from the Government of Japan' for 1981-82 (Yen 2.134 billion Grant Aid—Debt-relief).

V (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30.8.1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24.10.68 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5.10.1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31.5.1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12.10.1976.

V (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers

that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5.10.1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31.5.1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12.10.1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note.—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

## Section VI.—Miscellaneous provisions.

VI (i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions. The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI (iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under

“Terms of payment”. Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

#### VI (iv) Future Instructions.

The Licencee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1981-82 from Japan.

#### VI (v) Breach or violation.

Any breach of violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

#### VI. (vi) List of Annexures

Annexure-I	List of eligible source countries
Annexure-II	List of eligible commodities
Annexure-III	Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).
Annexure-IV	Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

#### ANNEXURE-I

##### List of Eligible Source Countries

#### A. OECD Countries

Australia  
Belgium  
Canada  
Denmark  
Finland,  
France,  
The Federal Republic  
of Germany  
Greece  
Iceland  
Ireland  
Italy  
Japan  
Luxembourg  
the Netherlands  
New Zealand  
Norway  
Portugal  
Spain  
Sweden  
Switzerland  
Turkey  
the United Kingdom and  
the United States.

#### B. Developing Countries & Territories

##### (b1) Non-O.P.C.E Developing countries

#### 1. AFRICA, North of Sahara

Egypt  
Morocco  
Tunisia

#### II. AFRICA, South of Sahara

Angola  
Botswana

Burundi  
Cameroon  
Cape Verde Islands  
Central African Rep  
Chad  
Comoro Islands  
Congo, People's  
Republic of Dahomey (1)  
Equatorial Guinea  
Ethiopia  
Gambia  
Ghana  
Guinea  
Ivory Coast  
Kenya  
Lesotho  
Liberia  
Malagasy Republic  
Malawi  
Mali  
Mauritania  
Mauritius  
Mozambique  
Niger  
Portuguese Guinea  
Reunion  
Rhodesia  
Rwanda  
St. Helena and dep (2)  
Sao Tome and Principe  
Senegal  
Seychelles  
Sierra Leone  
Somalia  
Sudan  
Swaziland  
Togo, Afars and  
Issas  
Togo  
Uganda  
Un. Rep. of Tanzania  
Upper Volta  
Zaire Republic  
Zambia

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
- (3) Main Islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit, St. Martin (Southern Part).

#### III. AMERICA, North and Cent.

Bahamas  
Barbadoses  
Belize  
Bermuda  
Costa Rica  
Cuba  
Dominican Republic  
El Salvador  
Guadeloupe  
Guatemala  
Haiti  
Honduras  
Jamaica  
Martinique

Mexico  
Netherlands & tiles  
Nicaragua  
Panama  
St. Pierre & Miquelon  
Trinidad and Tabago  
West Indies (Br.) n.i.e.  
(a) Associated States  
(b) Dependencies (2)

#### IV. AMERICA. South

Argentina  
Bolivia  
Brazil  
Chile  
Colombia  
Falkland Islands  
French Guiana  
Guyana  
Paraguay  
Peru  
Surinam  
Uruguay

#### V. ASIA Middle East

Bahrain  
Israel  
Jordan  
Lebanon  
Oman  
Syrian Arab Republic  
United Arab Emirates (3)  
Yemen Arab Republic  
Yemen, People's D.R. (4)

#### VI. ASIA South

Afghanistan  
Bangladesh  
Bhutan  
Burma  
Maldivis  
Nepal  
Pakistan  
Sri Lanka

#### VII. ASIA Far East

Borneo  
Hong Kong  
Khmer Republic  
Korea, Republic of Laos  
Macao  
Malaysia  
Phillippines  
Singapore  
Taiwan  
Thailand  
Timer  
Vietnam, Rep. of  
Viet-Nam Dem. Rep.

- (1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands : Montserrat, Gayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Ummel al Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Island (including Tahiti) the

Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

- (6) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands  
Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

#### VIII. OCEANIA

Cock Islands  
Fiji  
Gilbert & Ellice Is.  
French Polynesia (5)  
Nauru  
New Caledonia  
New Hebrides (Br. and Fr.)

#### Hicu

Pacific Islands (US) (6)  
Papua New Guinea  
Solomon Islands (Br.)  
Tongo  
Wallis and Futuna  
Western Samoa

#### IX. EUROPE

Cyprus  
Gibraltar  
Greece  
Malta S  
Spain  
Turkey  
Yugoslavia

#### (b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria  
Bolivia  
Libyan ab Rdpublic  
Gabon  
Nigeria  
Ecuador  
Venezuela  
Iran  
Iraq  
Kuwait  
Qatar  
Saudi Arabia  
Abu Dhabi  
Indonesia

## ANNEXURE II

### Eligible Commodity List

1. Rolls
2. Steel including special steel and alloy steel
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors
4. Chemicals
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures
6. Components, attachments and spares for power tillers
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials

8. Machinery and equipment for the Small Scale Sector
9. Machinery, equipment and spares for the Oil and Natural Gas sector
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

## ANNEXURE III

"Request for issue of the authorisation to pay"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street,  
New Delhi-110001.

Subject.—Import from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 2.134 billion for 1981-82.

Sir,

In connection with the import of \_\_\_\_\_ from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen, if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) or which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and Address of the supplier.
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

Yours faithfully,

## ANNEXURE IV

No.

## GOVERNMENT OF INDIA

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,  
Tokyo Branch,  
Tokyo (Japan).

Subject.—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.134 billion Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13.3.1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen ..... to M/s. .... (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo/Importers Bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. The A/P will remain valid upto .....

Yours faithfully,  
Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer ..... with reference to their letter No. .... dated .....

2. Importer's Banker ..... they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen[US]£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17.1.1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16.6.1976. The interest is payable on both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 23-ITC(PN)/68 dated 24.10.1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5.10.1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31.5.74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12.10.1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and

Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1981-82 (Yen 2.134 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5.10.1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24.10.1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)

